किस्सा चार निर्वासित दरवेशों का

दिवाली के पूर्व संध्या पर भाजपा के चार बूढ़े एक बूढ़े के घर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक लिखित बयान जारी कर दिया। बयान जितना प्रेस और जनता के लिये था उतना ही पार्टी के लिये भी। खासकर यह भाजपा की रंगा-बिल्ला की जोड़ी को संबोधित और लक्षित था।

बयान जारी करने के दो दिन पहले बिहार विधानसभा के परिणाम आये थे और रंगा-बिल्ला की जोड़ी को मुंह की खानी पड़ी थी। बिहार के नये जय-वीरू ने रंगा-बिल्ला को धोबिया पाट दे मारा था। पर रंगा-बिल्ला इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और भाजपा में उनके चमचे उन्हें बचाने के लिये सामूहिक जिम्मेदारी की बात करने लगे थे। चुनावों के दौरान जिस सामूहिक शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ था और जो पिछले डेढ साल से भाजपा के शब्दकोश से गायब था अचानक वह शब्द सबकी जुबान पर चढ़ गया था। इसके पहले भाजपा की हर जीत का श्रेय रंगा-बिल्ला ही लेते रहे थे और उनके चमचे उन्हें यह श्रेय सहर्ष देते रहे थे।

रंगा-बिल्ला की जोड़ी ने भाजपा के उपरोक्त बूढ़ों को सत्ताशीन होते ही निर्वासित कर दिया था। इस निर्वासन को मार्गदर्शक मंडल नाम से सजाने का प्रयास भी किया गया था। पर बूढ़े अपने जीते जी अपना क्रिया-क्रम करने या होने देने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने तरह-तरह से अपनी नाखुशी जाहिर की थी। उनमें से एक ने तो इस निर्वासन को 'ब्रेन डेड' की घोषणा के बराबर करार दिया था।

पूंजीवादी राजनीति की रीति-नीति से भली-भांती परिचित इन बूढ़ों को उम्मीद थी कि उनके दिन फ़िरेंगे। यदि हर कुत्ते के दिन फ़िरते हैं तो ये तो फ़िर भी भाजपा के बूढे थे और 'ब्रेन डेड' भी नहीं। बल्कि इनका ब्रेन पर्याप्त था और मौके की तलाश में था। और अब मौका हाथ में आ गया है।

भाजपा के इन निर्वासित बूढ़ों ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने किसी रहस्य की गुंजाइश नहीं छोड़ी। भाजपा की रग-रग से परिचित इन बूढ़ों को पता था लाग-लपेट से की गयी बात के फ़ंदे से रंगा-बिल्ला आसानी से बच निकलेंगे। वे इनकी गाली को उनका आशीर्वचन घोषित कर डालेंगे। इसीलिये इन बूढ़ों ने व्याकरण की भाषा में बात करें तो व्यंजना के बदले अमिधा (शब्द के तीन शक्तियों में से एक। वह शक्ति जिसके द्वारा शब्दों से सीधा-सादा अर्थ निकले-सं) का इस्तेमाल किया जिससे राजनीति के दुधमुंहे बच्चों को भी पता चल जाये कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की हार की जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर तय की जानी चाहिये। इसे सामूहिकता की आड़ में टाला नहीं जाना चाहिये। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग जीत की अवस्था में जीत का व्यक्तिगत श्रेय लेते वे हार की अवस्था में इसे समूह पर डाल रहे हैं। इशारा साफ़ था। जीत होती तो श्रेय रंगा-बिल्ला को जाता और अब हारने पर सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जा रही है। बूढ़े यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा में आवाजें घुट गयी हैं। यानी रंगा-बिल्ला ने अपने चमचों की मदद से विरोधी आवाज़ों का गला घोंट डाला है।

यह बयान भाजपा के बूढ़ों का विद्रोह था। यह विद्रोह उन बूढ़ों का था जो एक तख्तापलट के द्वारा सत्ता से वंचित कर दिये गये थे। इतना ही नहीं उन्हें स्वयं निर्वासित होने की गरिमा से भी वंचित कर दिया गया था। एक बूढ़ों को जो दस साल से दिल्ली की गद्दी पर बैठने का इंतजार कर रहा था, और भी ज़्यादा मलाल इसलिये भी था कि रंगा उसी का संरक्षित था और 2002 के नरसंहार के बाद तो उसी ने रंगा के राजनीतिक जीवन को बचाया था। वह रंगा प्राचीन भारत के इतिहास से भली-भांति परिचित था और समय आने पर उसने तख्तापलट में ज़रा भी संकोच नहीं किया। सत्ता के लिये हज़ारों की शारीरिक हत्या करवाने वाले रंगा को भला कुछ लोगों की राजनीतिक हत्या से क्यों परेशानी होती।

बूढ़ों के दिवाली विद्रोह ने भाजपा में कुछ खलबली मचाई। इसके प्रभाव में कुछ अधबूढ़ों और जवानों ने भी साहस दिखाया। पर रंगा-बिल्ला अभी सत्ता पर मजबूती से काबिज हैं। यह विद्रोह उनके लिये बम के बदले दिवाली का पटाखा ही साबित हुआ।

भाजपा के बूढ़े इस उम्मीद में इंतज़ार कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये पटाखे इकट्ठे होकर बम बन जायेंगे और रंगा-बिल्ला को उड़ा देंगे। तब तक वे गाहे-बगाहे इकट्ठा होकर पुराने चार दरवेशों की तरह अपने-अपने किस्से एक दूसरे को सुना सकते हैं: धोखा देने और धोखा खाने के किस्से।

-नागरिक

संघी खाएगा स्वर्ग जाएगा !
अल्पसंख्यक खाएगा नरक जाएगा !

बीफ के सवाल पर जहाँ देश के अन्दर पीट.पीटकर लोगों को मार डाला जा रहा है या पशुधन के व्यापारियों की पिटाई करके जान ले ली जा रही हो। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी श्री मनमोहन वैद्य ने स्वीकार किया है कि संघ के लोग बीफ खाकर भी उसमें रह सकते हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार संघ के 3000 लोग बीफ का आनंद लेते हैं। संघ के लोग हिन्दी भाषी प्रदेश में बीफ के सवाल को लेकर समाज में कटुता पैदा करते हैं वहीं स्वयं उसका सेवन करने से परहेज नहीं करते हैं यह उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। मुख्य सवाल यह है कि इनके दोहरे चरित्र के कारण देश के अन्दर निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भयभीत होते हैं। दूसरी तरफ यह लोग भी बीफ के सवाल पर तमाम सारी पूर्वाग्रह भरी बातें कर धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। मनमोहन वैद्य के बीफ खाने की बात स्वीकार करने के बाद भी संघ के लोग उन्माद फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि नागपुर मुख्यालय को बीफ के सवाल के ऊपर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए तथा गौरक्षा समिति से लेकर तमाम सारी सेनायें उन्होंने बना रखी है उसको भंग करें। अन्यथा उनकी दोगली राजनीति के कारण देश के एकता और अखण्डता विविधता को गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है।

.रणधीर सिंह सुमन
लो क सं घ र्ष !

ठग रेलमंत्री और बुलेट प्रधानमंत्री

ये है ट्रेन की जनरल बोगी का हाल

जापानी प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा में सन 2022 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने के समझौते को राष्ट्रीय गर्व के रूप में पेश किया जा रहा है। 98 हजार करोड़ रुपये में मुम्बई से अहमदाबाद के बीच मोदी की बुलेट ट्रेन चलेगी जबकि दोनों शहरों के बीच इससे तीन गुणा तेज हवाई यात्रा पहले से मौजूद है। 12 हजार मानव.रहित रेल क्रासिंग पर हर वर्ष हजारों अकाल मौतें होती हैं जबकि इन पर भूमिगत रास्ता या ओवर ब्रिज बनाने का कुल खर्च मात्र 50.60 हजार करोड़ रुपये आएगा। वाह रे चायवाले प्रधानमन्त्री तूने अपनी निजी जिद को राष्ट्रीय गर्व बनाकर परोस दिया !

रेल मंत्री सुरेश प्रभु को एक महानायक बना कर पेश किया जा रहा है जो रेलवे को सारी झंझटों से निजात दिलाकर उसे 21वीं शताब्दी की आधुनिकतम व्यवस्था में बदल देंगे। जोर शोर से यह प्रचारित किया जाता है कि कैसे चलती ट्रेन में किसी स्त्री की सुरक्षा गुहार या यात्री के गन्दगी की शिकायत या बच्चे की भूख की जरूरत की भनक लगते ही त्वरित कार्यवाही की गयी । पर वास्तविकता बेहद निराशाजनक ही नहीं बल्कि डरावनी भी है। न ट्रेन वक्त पर चल रही हैं और न टिकटों की कालाबाजारी पर कोई रोक लगी है । रेल का खान.पान मंहगा होता गया है और गन्दगी बढ़ती गयी है। यहाँ तक कि नयी भर्तियों पर रोक लगाकर लाखों कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रम भी बेतरह कम किये जा रहे हैं ।

2013 में रेल किराये को डीजल की कीमतों से जोड़ा गया था। तब से ज्यों.ज्यों डीजल की कीमतों में वृद्धि हुयी, किराये भी तद्नुसार बढ़ाये गए। पर अब डेढ़ वर्ष से डीजल की कीमतें घटते.घटते एक तिहायी रह गयी हैं, फ़िर भी किरायों में कोई कटौती नहीं की जा रही है। यह एक तरह से आपराधिक धोखाधड़ी से कम नहीं जो सुरेश प्रभु के आशीर्वाद से ही चल रही है। लगता है जनता की जेब पर डाका मारना ही हाई.टेक संचालन है।

चाय वाला प्रधानमन्त्री और हाई.टेक रेल मंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल और रेल यात्री क्या-क्या भुगतेंगे, देश को क्या.क्या कीमत चुकता करनी होगी। इस पर अब पर्दा रखने की जरूरत भी मोदी सरकार महसूस नहीं करती।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 1-15 दिसम्बर 2015 का अंक मिला जिसमें राजनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। बिहार विधान सभा के चुनावों के परिणाम का महागठबन्धन व एनडीए विशेषकर चुनावी रणनीतियों के सन्दर्भ में उपयुक्त विश्लेषण किया गया है। इन परिणामों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि पूरे देश में मोदी सरकार के प्रति असंतोष की आग सुलग रही है जो उपयुक्त समय आने पर भड़क पड़ेगी तथा मोदी व अमित शाह की तानाशाही के विरुद्ध भाजपा में भी असंतोष मुखर होने लगा है जिसे आरएसएस दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मोदी को भाजपा की अन्दरूनी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी मोदी अपनी विदेश यात्रा तथा मीडिया के ज़रिए अपनी छवि निर्माण में लगा हुआ है। बिहार विधान सभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में रतलाम लोकसभा उपचुनाव तथा गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनावों के परिणामों से स्पष्ट उज़ागर होता है कि मोदी व भाजपा का करिश्मा धुमिल हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भाजपा के लिये रतलाम लोकसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न था जिसके लिये शिवराज सिंह चौहान ने अपना पूरा ज़ोर लगा रखा था, परन्तु कांग्रेस ने भाजपा को हराकर उस सीट पर विजय प्राप्त की।

मोदी व चुनावी रणनीतिकार अमितशाह के गृह राज्य गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। भाजपा के लिये सबसे बड़ा झटका इसलिये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र मेहसाणा में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि भाजपा ने सभी छ: नगर निगमों में पुन: विजय प्राप्त की है, परंतु पिछले चुनावों के मुकाबले में भाजपा को वहां इस बार कम सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या बढी है। राजकोट नगर निगम में तो कांग्रेस ने 34 सीटें जीती जबकि भाजपा को 38 सीटें मिली, स्पष्ट है कि मुकाबला लगभग बराबर का रहा। ज़िला और ताल्लुक पंचायतों में कांग्रेस ने भाजपा को बहुत भारी झटका दिया। कांग्रेस ने 231 ताल्लुक पंचायतों में से 132 पर विजय प्राप्त की जबकि 25 ताल्लुक पंचायतों के चुनाव परिणाम मीडिया में नहीं आए और 31 ज़िला पंचायतों में से 21 पर विजय प्राप्त की। गौरतलब है कि कांग्रेस ने तीन चौथाई ज़िला पंचायतों तथा 60 प्रतिशत ताल्लुक पंचायतों पर अधिकार किया और शहरी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढाया है।

भाजपा ने इस भारी पराजय से सबक लेने के बजाए, हार की ठीकरा हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन पर फ़ोड़ दिया। परंतु चुनाव परिणामों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हार्दिक पटेल के गृह क्षेत्र में भाजपा को विजय मिली है तथा पाटीदार आन्दोलन से प्रभावित मुख्य क्षेत्र वदोदरा, अहमदाबाद और सूरत में कांग्रेस को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इन चुनाव परिणामों ने मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। परंतु नरेन्द्र मोदी का सशक्त विश्वसनीय विकल्प तैयार करने के लिये कुनबा-परस्ती की राजनीति से बचना होगा। शराब पीने से दलित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा विशेषकर महिलाओं पर हो रहे कुप्रभाव को मद्देनज़र विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शराब बन्दी की जाती है। हालांकि शराब बंदी से महिलाएं तो खुश होती हैं परन्तु व्यवहारिक रूप में नेताओं व पुलिस की आपसी मिलीभगत से शराब का अवैध व्यापार शुरू हो जाता है जबकि राज्य सरकार के राजस्व की हानी होती है, जिसके ज्वलंत उदाहरण हैं-गुजरात, हरियाणा, आदि राज्यों में शराब बन्दी। इनसे सबक न लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बिहार में शराब बन्दी की घोषणा की है जिसका स्तम्भ 'खबर दार बिहार में शराब बन्दी का गुजरात मॉडल!' में काल्पनिक साक्षात्कार के ज़रिए खुलासा किया गया है।

सुनपेड़ कांड के तथाकथित पीड़ित दलित परिवार व आरोपी राजपूत परिवारों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश के मद्देनज़र सुनपेड़ कांड की वास्तविकता का लेख 'सुनपेड़ कांड: कौन करे इस न्याय व्यवस्था पर विश्वास-वकीलों की हड़ताल से उठा मुद्दा' के ज़रिए खुलासा करने का साहस किया गया है, जबकि मीडिया, प्रशासन तथा पुलिस ने जितेन्द्र द्वारा 'दलित' का कवच धारण किए परिवार के कथन को बिना किसी जांच के उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों को आरोपी बना दिया। इस मामले में तथाकथित आरोपी वकीलों को भी नहीं बख्शा गया। इससे पुलिस व न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है। वोट बैंक की राजीनीति के कारण यह सारा खेल स्थानीय पुलिस व सीबीआई के द्वारा जातिगत राजनीति के नाम पर चलाया जा रहा है। हालांकि राजपूतों की महापंचायत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक प्रस्ताव द्वारा सीबीआई से इस कांड की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों को सज़ा देने की अपील की है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सिटी एक्ट के ज़रिए केन्द्रीय विश्व विद्यालयों की संरचना और तौर-तरीकों में आए जा रहे बदलाव, विश्वविद्यालय के सिलेबस के प्रस्तावित मानकीकरण और केन्द्रीकरण की नीति लागू करने के बाद उत्पन्न शैक्षिक स्थिति का लेख 'विश्वविद्यालयों के धंधेबाज़ी की नयी तैयारी' में सटीक विश्लेषण किया गया है। परन्तु आशंका है कि आम आदमी को इस लेख को समझने में कठिनाई आएगी।

प्रधानमंत्री के बहुचर्चित व प्रचारित स्वच्छता अभियान का धरातल पर कोई ठोस असर नज़र नहीं आ रहा। स्वच्छता के लिये आवश्यक आधुनिक उपकरण व सफ़ाई कर्मियों की पर्याप्त संख्या के अभाव के कारण स्थानीय निकाय लाचार दिखाई देते हैं जिनका प्रमुख कर्त्तव्य सफ़ाई रखना है। परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती बल्कि केवल स्वच्छता अभियान के प्रचार पर ही सरकार के द्वारा भारी खर्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कानून बनाने के बावजूद दलितों द्वारा सिर पर मैला ढोने की परम्परा आज तक कायम है जिसका लेख 'स्वच्छता अभियान की पोल खोलते सर पर मैला ढोने वाले दलित' में पूरा खुलासा किया गया है।

स्तम्भ 'तुर्की ब तुर्की/हकीकत जबान पर आ गयी' के ज़रिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सन्दर्भ में जनता द्वारा कांग्रेस व भाजपा नेताओं को चोर, लुटेरे व डकैत समझने पर सटीक कटाक्ष किया गया है। शेष अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च स्तरीय व प्रशंसयनीय हैं।

-प्रो.जुगल किशोर गुप्ता